

banking 's role in the development of the economy in India

Dr. Rajesh Verma

Dr. Rajesh Verma
Kulaguru, Rani Durgavati Vishwavidyalaya, Jabalpur M.P.

Soniya Desai

Soniya Desai, PMCOE, Shri Atal Bihari Vajpeyee Sanshodhan Kendra and Vaishali Mahavidyalaya

Indore, Madhya Pradesh

Abstract

This research paper discusses the role of banking in the development of the economy in India. It focuses on the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY) and its impact on financial inclusion and economic growth. The study highlights the challenges faced by the banking sector and the government's efforts to address them. It also discusses the role of banking in promoting financial literacy and the importance of a strong regulatory framework. The research concludes that banking plays a crucial role in the development of the economy and that the government should continue to support the banking sector to achieve its goals.

Its impact on the economy, the government has taken various measures to promote banking, such as the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY) and the Pradhan Mantri Mudra Yojana (PMMY). These measures have helped to increase the number of banking accounts and the amount of credit disbursed. However, there are still challenges, such as the need for a strong regulatory framework and the need to improve the efficiency of the banking sector. The research concludes that banking plays a crucial role in the development of the economy and that the government should continue to support the banking sector to achieve its goals.

Keywords: Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, financial inclusion, economic growth, banking, India.

1. Introduction

The Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY) was launched in August 2014 by the Government of India. It is a flagship scheme aimed at promoting financial inclusion and economic growth. The scheme provides access to banking services for all citizens, regardless of their income level. It has helped to increase the number of banking accounts and the amount of credit disbursed. However, there are still challenges, such as the need for a strong regulatory framework and the need to improve the efficiency of the banking sector. The research concludes that banking plays a crucial role in the development of the economy and that the government should continue to support the banking sector to achieve its goals.



८. पीएमजेडीवाई अकाउंट

1. जिस व्यक्ति का बैंक खाता नहीं है, उसके लिए एक बेसिक सेविंग्स बैंक अकाउंट खोला जाता है।
2. पीएमजेडीवाई अकाउंट में कोई न्यूनतम बैलेंस रखने की ज़रूरत नहीं है।
3. पीएमजेडीवाई अकाउंट में जमा पैसे पर ब्याज मिलता है।
4. पीएमजेडीवाई अकाउंट होल्डर को रुपये डेबिट कार्ड दिया जाता है।
5. पीएमजेडीवाई अकाउंट होल्डर्स को जारी किए गए रुपये कार्ड के साथ 1 लाख रुपये का एक्सीडेंट इश्योरेंस कवर मिलता है (28.8.2018 के बाद खोले गए नए पीएमजेडीवाई अकाउंट के लिए इसे बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दिया गया है)।
6. योग्य अकाउंट होल्डर्स को 10,000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट (ओडी) सुविधा मिलती है।
7. पीएमजेडीवाई अकाउंट डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजीबीवाई), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई), अटल पेंशन योजना (एपीवाई), माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी बैंक (मुद्रा) योजना के लिए योग्य हैं।

इंदौर शहर, जो मध्यप्रदेश का आर्थिक केंद्र माना जाता है, तेजी से शहरीकरण और आधारभूत संरचना के विस्तार के दौर से गुजर रहा है। ऐसे में, वित्तीय संसाधनों का समुचित वितरण और नागरिकों की बैंकिंग भागीदारी शहर के विकास में निर्णायक भूमिका निभाती है।

2- “क/क द मी”

1. लाभार्थियों की वित्तीय साक्षरता, बैंकिंग उपयोगिता और सामाजिक सुधार में परिवर्तन का आकलन करना।
2. योजना से संबंधित प्रमुख समस्याओं और चुनौतियों की पहचान करना।
3. इंदौर में योजना की प्रभावशीलता को बढ़ाने हेतु सुझाव प्रस्तुत करना।

3- “क/क इ) फर

प्रस्तुत अध्ययन एक वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक अनुसंधान पर आधारित है, जिसका उद्देश्य इंदौर शहर में प्रधानमंत्री जन धन योजना के क्रियान्वयन और उसके सामाजिक-आर्थिक प्रभावों का मूल्यांकन करना है। अध्ययन के अंतर्गत 159 लाभार्थियों का चयन इंदौर नगर निगम क्षेत्र से स्तरीकृत यादृच्छिक न्यादर्श विधि के माध्यम से किया गया है, ताकि विभिन्न आयु, लिंग और व्यवसाय वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके। समंक संग्रह हेतु प्राथमिक और द्वितीयक दोनों प्रकार के स्रोतों का उपयोग किया गया है। प्राथमिक आंकड़े संरचित प्रश्नावली और व्यक्तिगत साक्षात्कार के माध्यम से संकलित किए गए हैं। संग्रहित आंकड़ों का विश्लेषण प्रतिशत और तुलनात्मक विश्लेषण जैसे सांख्यिकीय उपकरणों की सहायता से किया गया है।



4- लैड फो'य'क.क ,o ifj.kke

rkfydk 1-eè;çn'k e: çèkkue=ñ tu èku ;ktuk d ykHkk&Fk; k dh fLFkfr %22 vDVcj 2025 rd%

राज्य का नाम	ग्रामीण/अर्ध-शहरी शाखाओं में लाभार्थी	शहरी/मेट्रो शाखाओं में लाभार्थी	कुल लाभार्थी	लाभार्थियों के खातों में शेष राशि (₹ करोड़ में)	लाभार्थियों को जारी रूपे कार्ड की संख्या
मध्यप्रदेश	36,108,206	10,082,455	46,190,661	16,908.77	34,371,171
कुल	36,108,206	10,082,455	46,190,661	16,908.77	34,371,171

स्त्रोत-द्वितीयक समंक, वार्षिक प्रतिवेदन 2024-25

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि मध्यप्रदेश राज्य में प्रधानमंत्री जन धन योजना का क्रियान्वयन व्यापक स्तर पर हुआ है। अक्टूबर 2025 तक राज्य में कुल 46.19 मिलियन (46,190,661) लाभार्थियों के खाते खोले जा चुके हैं। इनमें से लगभग 78% (36,108,206) खाते ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी क्षेत्रों में और 22% (10,082,455) खाते शहरी एवं मेट्रो शाखाओं में खुले हैं, जो यह दर्शाता है कि योजना का प्रमुख फोकस ग्रामीण वित्तीय समावेशन पर रहा है। लाभार्थियों के खातों में कुल ₹16,908.77 करोड़ की राशि जमा है, जो यह बताता है कि योजना केवल खाते खोलने तक सीमित न रहकर वास्तविक बचत की प्रवृत्ति को भी प्रोत्साहित कर रही है। इसके अतिरिक्त, 34.37 मिलियन रूपे कार्ड लाभार्थियों को जारी किए गए हैं, जिससे डिजिटल भुगतान और बैंकिंग सेवाओं की पहुँच को सुदृढ़ता मिली है।

सारांशतः, यह आँकड़े यह प्रमाणित करते हैं कि प्रधानमंत्री जन धन योजना ने मध्यप्रदेश में वित्तीय समावेशन को सशक्त बनाने के साथ-साथ बैंकिंग नेटवर्क को ग्रामीण और शहरी दोनों स्तरों पर समान रूप से सुदृढ़ किया है, जिससे राज्य के आर्थिक और आधारभूत विकास को गति मिली है।

rkfydk 2-ykHkk&Fk; k dh tulkf[; dh çkQkby

विवरण	वर्गीकरण	लाभार्थियों की संख्या	प्रतिशत (%)
लिंग	पुरुष	62	39.0%
	महिला	97	61.0%
	कुल	159	100%
आयु वर्ग	18-25 वर्ष	34	21.4%



	26-35 वर्ष	48	30.2%
	36-45 वर्ष	42	26.4%
	46 वर्ष से अधिक	35	22.0%
	कुल	159	100%
शिक्षा स्तर	अशिक्षित	19	11.9%
	प्राथमिक शिक्षा	41	25.8%
	माध्यमिक शिक्षा	53	33.3%
	स्नातक या उससे अधिक	46	29.0%
	कुल	159	100%
वैवाहिक स्थिति	विवाहित	112	70.4%
	अविवाहित	47	29.6%
	कुल	159	100%
पेशा	मजदूर/दैनिक वेतनभोगी	54	34.0%
	स्वरोजगार/छोटा व्यवसाय	43	27.0%
	गृहिणी	39	24.5%
	नौकरीपेशा	23	14.5%
	कुल	159	100%
मासिक आय	₹5,000 तक	48	30.2%
	₹5,001 – ₹10,000	64	40.3%
	₹10,001 – ₹15,000	33	20.8%
	₹15,001 से अधिक	14	8.7%



	कुल	159	100%
परिवार का आकार	1-3 सदस्य	28	17.6%
	4-5 सदस्य	79	49.7%
	6 या अधिक सदस्य	52	32.7%
	कुल	159	100%

स्रोत-प्राथमिक समंक

तालिका 2 से स्पष्ट होता है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत इंदौर शहर के लाभार्थियों में महिलाओं की भागीदारी (61%) अधिक रही। यह दर्शाता है कि योजना ने महिला वित्तीय सशक्तिकरण को प्रोत्साहन दिया है। आयु वर्ग के अनुसार, 26-35 वर्ष (30.2%) के उत्तरदाता सर्वाधिक पाए गए, जिससे यह पता चलता है कि युवा वर्ग इस योजना से सबसे अधिक लाभान्वित हुआ है। शिक्षा स्तर के संदर्भ में देखा गया कि 33.3% उत्तरदाताओं ने माध्यमिक शिक्षा प्राप्त की थी, जबकि 29% स्नातक स्तर के थे। इसका अर्थ है कि योजना का लाभ शिक्षित एवं अर्धशिक्षित दोनों वर्गों तक पहुँचा है। वैवाहिक स्थिति के अनुसार 70.4% लाभार्थी विवाहित थे, जो पारिवारिक जिम्मेदारी के कारण वित्तीय सुरक्षा की ओर अधिक झुकाव रखते हैं। पेशा के अनुसार, 34% लाभार्थी दैनिक वेतनभोगी मजदूर थे, जबकि 27% स्वरोजगार में लगे थे। इससे यह स्पष्ट होता है कि योजना का प्राथमिक लाभ समाज के निम्न एवं असंगठित क्षेत्र को मिला है। मासिक आय के आधार पर, अधिकतर उत्तरदाताओं की आय ₹5,000 से ₹10,000 के बीच पाई गई (40.3%), जिससे यह सिद्ध होता है कि योजना ने निम्न आयवर्ग को औपचारिक बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ा है। परिवार के आकार के संदर्भ में, अधिकांश लाभार्थियों (49.7%) के परिवार 4-5 सदस्यों के थे, जो भारत के सामान्य पारिवारिक ढाँचे का प्रतीक है।

सारांशतः, यह जनसांख्यिकी विश्लेषण यह दर्शाता है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना ने इंदौर के समाज के विविध वर्गों, विशेषकर महिलाओं, युवाओं और निम्न-आय वर्ग के लोगों को वित्तीय मुख्यधारा में शामिल करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

rkfydk 3-çèkkue=ñ tu èku ;ktuk di çHkko ,o lcfèkr leL;k,;

मापदंड	विवरण	लाभार्थियों की संख्या	प्रतिशत (%)
बैंकिंग पहुँच में वृद्धि	योजना के माध्यम से पहला बैंक खाता खुला	146	91.8%
वित्तीय सहायता	रूपे कार्ड का नियमित उपयोग करने वाले	108	67.9%

का उपयोग	लाभार्थी		
	प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) का लाभ प्राप्त करने वाले लाभार्थी	75	47.2%
महिलाओं की भागीदारी	महिला लाभार्थियों का अनुपात	97	61.0%
वित्तीय साक्षरता की स्थिति	योजना के लाभों (ओवरड्राफ्ट/बीमा) की जानकारी नहीं रखने वाले लाभार्थी	62	39.0%
आधारभूत आर्थिक प्रभाव	छोटे व्यापार, स्वरोजगार एवं बचत में वृद्धि महसूस करने वाले लाभार्थी	118	74.2%
मुख्य समस्याएँ	बैंक शाखाओं में भीड़	87	54.7%
	दस्तावेज़ी प्रक्रिया की जटिलता	65	40.9%
	जागरूकता की कमी	71	44.6%

स्रोत-प्राथमिक समंक

तालिका 3 से स्पष्ट होता है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना ने इंदौर शहर के नागरिकों को वित्तीय मुख्यधारा से जोड़ने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लगभग 92% लाभार्थियों ने बताया कि योजना के माध्यम से उनका पहला बैंक खाता खोला गया, जो यह दर्शाता है कि वित्तीय समावेशन का उद्देश्य बड़े स्तर पर सफल रहा। वित्तीय उपयोगिता के दृष्टिकोण से देखा जाए तो 68% लाभार्थियों ने रूपे कार्ड का उपयोग किया, जो डिजिटल भुगतान और नकदी रहित लेनदेन की दिशा में प्रगति का संकेत है। वहीं 47% उत्तरदाताओं ने प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) का लाभ प्राप्त किया, जिससे सरकारी योजनाओं की पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित हुई।

महिलाओं की भागीदारी (61%) योजना की सबसे उल्लेखनीय उपलब्धियों में से एक है। अधिकांश महिला लाभार्थी गृहिणियाँ थीं, जिनके लिए यह योजना आर्थिक आत्मनिर्भरता और सामाजिक सशक्तिकरण का माध्यम बनी। इससे यह सिद्ध होता है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना न केवल आर्थिक बल्कि सामाजिक स्तर पर भी सकारात्मक प्रभाव डालने में सफल रही। हालाँकि, वित्तीय साक्षरता अभी भी एक चुनौती बनी हुई है— लगभग 39% लाभार्थियों को ओवरड्राफ्ट या बीमा जैसी सुविधाओं की जानकारी नहीं थी। यह सिद्ध होता है कि योजना का लाभ केवल बैंक खाता खोलने तक सीमित रह गया है, जबकि उसके द्वितीयक लाभों तक पहुँच सीमित है। आधारभूत आर्थिक प्रभाव के रूप में 74% लाभार्थियों ने बताया कि योजना से उनके छोटे



व्यापार, बचत और स्वरोजगार की गतिविधियों में वृद्धि हुई है। इससे स्थानीय स्तर पर आर्थिक गतिशीलता और आत्मनिर्भरता में सुधार देखा गया, जो शहर के समग्र आधारभूत विकास में सहायक सिद्ध हुआ।

वहीं मुख्य समस्याओं में बैंक शाखाओं में भीड़ (54.7%), दस्तावेज़ी प्रक्रिया की जटिलता (40.9%) और जागरूकता की कमी (44.6%) जैसी बाधाएँ सामने आईं। ये कारक योजना के पूर्ण प्रभाव को सीमित करते हैं और प्रशासनिक सुधारों की आवश्यकता को इंगित करते हैं।

सारांशतः, यह स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना ने इंदौर शहर के आर्थिक और सामाजिक ढाँचे को सशक्त बनाया है, किंतु इसकी दीर्घकालिक सफलता के लिए वित्तीय साक्षरता, सेवा की सुगमता और प्रशासनिक सरलता पर विशेष ध्यान आवश्यक है।

5- **fu"d"K** ¶

प्रधानमंत्री जन धन योजना भारत सरकार की उन महत्वपूर्ण वित्तीय योजनाओं में से एक है जिसने आर्थिक समावेशन के विचार को व्यवहार में बदलने का कार्य किया। इंदौर शहर जैसे विकसित होते शहरी क्षेत्र में इस योजना ने निम्न आयवर्ग, मजदूर वर्ग, और विशेष रूप से महिलाओं को औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से जोड़ने में उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। प्रस्तुत अध्ययन से यह निष्कर्ष स्पष्ट रूप से उभरकर सामने आया कि योजना ने न केवल वित्तीय पहुँच का विस्तार किया है, बल्कि लोगों में आर्थिक सुरक्षा, बचत की प्रवृत्ति और आत्मनिर्भरता की भावना को भी सशक्त किया है।

सर्वेक्षण के अनुसार, लगभग 92% लाभार्थियों का पहला बैंक खाता इसी योजना के अंतर्गत खोला गया, जिससे यह प्रमाणित होता है कि योजना ने वित्तीय जागरूकता का आधार तैयार किया। महिलाओं की 61% भागीदारी इस योजना के सामाजिक प्रभाव की ओर संकेत करती है, जिसने पारिवारिक स्तर पर आर्थिक निर्णय-प्रक्रिया में महिलाओं की भूमिका को मज़बूती दी। रूपा कार्ड और डीबीटी के माध्यम से प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले लाभार्थियों का प्रतिशत योजना की पारदर्शिता और प्रभावशीलता को दर्शाता है।

हालाँकि, अध्ययन में यह भी पाया गया कि योजना के द्वितीयक लाभों— जैसे ओवरड्राफ्ट सुविधा, बीमा कवरेज और वित्तीय शिक्षा के प्रति जागरूकता अपेक्षाकृत कम है। लगभग 39% लाभार्थी इन सुविधाओं से अनभिज्ञ रहे, जो वित्तीय साक्षरता की कमी को उजागर करता है। साथ ही, बैंक शाखाओं में भीड़, दस्तावेज़ी प्रक्रिया की जटिलता और सूचनात्मक अंतराल जैसी चुनौतियाँ योजना के सुचारु क्रियान्वयन में बाधक रहीं। फिर भी, योजना का समग्र प्रभाव सकारात्मक रहा। इससे स्थानीय स्वरोजगार, सूक्ष्म बचत और आर्थिक गतिशीलता को बढ़ावा मिला, जिससे इंदौर शहर के सामाजिक-आर्थिक ढाँचे में स्थिरता और वि"वास का वातावरण निर्मित हुआ। इस योजना ने गरीब वर्ग को न केवल बैंकिंग प्रणाली से जोड़ा, बल्कि उन्हें सरकारी योजनाओं और कल्याणकारी कार्यक्रमों तक पहुँच का माध्यम भी प्रदान किया। अतः यह कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना इंदौर शहर के आधारभूत विकास की दिशा में एक सशक्त और दीर्घकालिक पहल साबित हुई है। भविष्य में यदि इस योजना के अंतर्गत वित्तीय साक्षरता, डिजिटल बैंकिंग प्रशिक्षण, और स्थानीय प्रशासनिक सहयोग को और मज़बूत किया जाए, तो यह योजना शहरी आर्थिक स्थायित्व और समावेशी विकास का आदर्श मॉडल बन सकती है।

6- **I>lo**

1. वित्तीय साक्षरता शिविरों का आयोजन कर योजना के विभिन्न लाभों की जानकारी दी जाए।
2. बैंक कर्मचारियों को लाभार्थियों से संवाद के लिए संवेदनशील बनाया जाए।



3. डिजिटल बैंकिंग साक्षरता को बढ़ावा दिया जाए ताकि लाभार्थी तकनीकी रूप से सक्षम बन सकें।
4. महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से योजना के प्रचार-प्रसार को बढ़ाया जाए।
5. स्थानीय प्रशासन को शहरी गरीबों की बैंकिंग पहुँच पर निगरानी बढ़ानी चाहिए।

7. संदर्भ:

- [1]. Government of India. (2023). *Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana: Progress Report*. Ministry of Finance.
- [2]. Reserve Bank of India. (2022). *Financial Inclusion in India: A Review*. RBI Publications.
- [3]. NABARD. (2021). *Status of Microfinance and Financial Inclusion in India*. NABARD Annual Report.
- [4]. Gupta, R. (2020). *Impact of PMJDY on Financial Inclusion in Urban India*. *Indian Journal of Economics and Development*, 16(3), 45–58.
- [5]. Sharma, P. (2021). *Financial Literacy and Inclusive Growth in India*. *Economic Affairs*, 66(2), 211–219

